भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

5 अप्रैल 2011

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो!

शोषण-उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हिंसा, अत्याचार और अपमान से भरी मौजूदा अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंककर जनता की जनवादी राजसत्ता की स्थापना हेतु जनयुद्ध को तेज करो!

पांच राज्यों - असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिच्चेरी और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए चुनावों का ढकोसला शुरू हो गया। जहां सारा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, संसाधनों की लूट, विस्थापन, पर्यावरण का विनाश आदि समस्याओं से दो चार है, वहीं सभी संसदीय पार्टियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है ताकि जनता को फिर एक बार धोखा देकर इन राज्यों में सत्ता हथियाई जा सके। देश में साम्राज्यवाद-निर्देशित आर्थिक नीतियों को लागू करने में आगे रहने वाली प्रमुख शोषक वर्गीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा समेत; सीपीएम जो पिछले 30 सालों से पश्चिम बंगाल में फासीवादी शासन लागू करती आ रही है; डीएमके और अन्ना डीएमके जो भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए खासा बदनाम हैं; असम की जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ गद्दारी करने वाला असम गण परिषद वगैरह पार्टियां मुख्य रूप से इन राज्यों में सत्ता पर कब्जा करने के लिए मैदान में हैं। सभी नेता धन बल, बाहु बल, जाति, धर्म आदि हथियारों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं ताकि वोट बटोर लिए जा सके। फूहड़ता की हदें पार कर मतदाताओं को साड़ियों से लेकर कम्प्यूटर तक कुछ भी दे देने का आश्वासन देने में एक दूसरे को मात दे रहे हैं। करोड़ों रुपए का धन बहाकर 'वोटों को खरीदने' की कोशिशों में लगे हुए हैं।

पिछले 30 सालों से पश्चिम बंगाल में सामाजिक फासीवादी शासन चलाती आ रही सीपीएम ने सामंती, साम्राज्यवादी व दलाल नौकरशाह पूंजीवादी लूटखसोट का समर्थन कर खुद को जनता की नजरों में नंगा कर लिया। टाटा, जिंदल जैसे दलाल पूंजीपतियों के हित में तथा एसईजेड के नाम से किसानों की जमीनें छीनने की कोशिशों के खिलाफ नंदीग्राम और सिंगूर में आंदोलन छेड़ने वाली जनता पर तथा लालगढ़ इलाके में पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ उमड़े जन सैलाब के ऊपर सीपीएम ने पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अपनी गुण्डा सेना 'हर्मद बाहिनी' के जरिए बर्बर दमन, अमानवीय हत्याकाण्ड और महिलाओं के साथ अत्याचारों का जो सिलसिला चलाया, वह इतिहास में काले धब्बा बनकर रह जाएगा। सीपीआई, फार्वर्ड ब्लॉक जैसी वाम मोर्चे की घटक पार्टियां सीपीएम की जन विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाली दिवालिया पार्टियों के रूप में जनता में नंगी होती जा रही हैं। सीपीएम के प्रति सभी वर्गों की जनता में सुलग रहे असंतोष और गुस्से का फायदा उठाकर ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस सत्ता हथियाने के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरकर आई है। इससे सीपीएम इस बार सत्ता के सुख से हाथ धोने का खतरा झेल रही है। आज ममता बनर्जी की कथनी चाहे जो भी हो, कल चुनाव जीतने के बाद जो शासन वह चलाएगी, वह सीपीएम से बुनियादी रूप से भिन्न नहीं रहेगा। यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेस से गठबंधन के बल पर ममता जो शासन लाएगी वह सामंतवाद व कार्पोरेट अनुकूल और जन विरोधी नीतियों की धारवाहिकता के रूप में ही होगा जिसे सीपीएम समेत तमाम अन्य शासक वर्गीय पार्टियां लागू करती आ रही थीं। कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम की तरह तृणमूल भी वही पार्टी है जो सामंती व दलाल पूंजीपति वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और जो साम्राज्यवाद के सामने नतमस्तक है। इसलिए बंगाल की जनता के सामने एक रास्ता बचता है कि वे इन ढोंगी चुनावों का बहिष्कार कर, लालगढ़ जनता के उज्ज्वल संघर्ष की प्रेरणा से माओवादी जनयुद्ध को केन्द्र में रखते हुए जुझारू जन संघर्षों का निर्माण करें। असली विकल्प यही है कि ऐतिहासिक लालगढ़ आंदोलन के परिणामस्वरूप भ्रूण रूप में अस्तित्व में आई वैकल्पिक जन राजसत्ता का और ज्यादा सुदृढ़ व जुझारू ढंग से विस्तार किया जाए।

तमिलनाडू मुख्यमंत्री करुणानिधि, पूर्व टेलिकॉम मंत्री ए. राजा और उनके डकैतों का गिरोह जिसने राज्य में सत्ता और केन्द्र में यूपीए गठबंधन में भागीदारी का फायदा उठाते हुए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए थे, अब फिर से प्रदेश में सत्ता हथियाने के लिए करोड़ों रुपए बहा रहा है। करुणानिधि सरकार ने तकरीबन 70 एसईजेड को मंजूरी देकर हजारों हेक्टेयर जमीनें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले कर दीं। किसानों और मजदूरों की जिंदगी दूभर बना दी। अकेले तिरपुर शहर में पिछले दो सालों में 25 हजार मजदूरों की नौकरियां छीन ली गईं जिसके परिणामस्वरूप दो हजार कपड़ा-मजदूरों ने खुदकुशी कर ली। वर्तमान में डीएमके के प्रति जनता में बढ़े हुए असंतोष का फायदा उठाते हुए जयललिता की अगुवाई वाली अन्ना द्रमुक किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। लेकिन गौरतलब है कि जयललिता भी कम बड़ी चोर नहीं है जिसका विगत में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हजारों करोड़ रुपए की सम्पत्तियां हासिल करने का इतिहास रहा है। तमिल राष्ट्रीयता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का दम्भ भरने वाली डीएमके और अन्ना डीएमके दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने श्रीलंका में सिंहली अंधराष्ट्रवादी राजपक्षे सरकार द्वारा एलटीटीई का सफाया करने के लक्ष्य से किए गए अन्यायपूर्ण युद्ध और तमिलों के

कत्लेआम का परोक्ष रूप से समर्थन किया था। अत: तमिलनाडू की जनता के सामने यही विकल्प है कि वह उक्त दो पार्टियों के साथ-साथ उनकी सभी सहयोगी पार्टियों को नकार कर जन आंदोलनों और क्रांतिकारी संघर्षों को तेज कर दे।

केरल में सीपीएम की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की सरकार कई घपलेबाजियों व घोटालों में लिप्त होकर कॉर्पोरेट वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए जनता में खासी बदनाम हो चुकी है। जनता के असंतोष का फायदा उठाते हुए वहां पर कांग्रेस-नीत गठबंधन यूडीएफ किसी न किसी तरीके से सत्ता पर काबिज होने के लिए कई पापड़ बेल रहा है। असम में असम गण परिषद, जिसका विगत में असमिया जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आंदोलन चलाने का इतिहास रहा है, आज राष्ट्रीय हितों के साथ गद्दारी कर सत्ता की होड़ में लगा हुआ है। उल्फा, बोडो आदि न्यायपूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का दमन करने में उसने कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर रखी है।

खासकर पिछले कुछ समय से देश में आए दिन घपलों और घोटालों के खुलासे होने लगे हैं, जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था का असली रूप दिन-ब-दिन साफ तौर पर सामने आ रहा है। हाल में उजागर होने वाले 2जी स्पेक्ट्रम आदि घोटालों से यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो गई कि किस तरह सभी पार्टियों के मंत्री, नेता, कॉर्पोरेट घरानों के मालिक और मीडिया सम्राट सांठगांठ कर लाखों करोड़ रुपए डकार रहे हैं। जहां एक तरफ अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाली विभिन्न तबकों की जनता, जन आंदोलनों और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लक्ष्य से लुटेरे शासक अपने सशस्त्र बलों के जरिए दमन अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फासीवादी कानूनों को तैयार कर जनता और आंदोलनकारियों को बिना किसी सुनवाई के सालों तक जेलों में बंद कर रहे हैं तथा उन्हें कठोर सजाएं दिलवा रहे हैं। कथित रूप से संविधान द्वारा प्राप्त जीने के अधिकार समेत जनता के तमाम बुनियादी अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

इन चुनावों को 'सुचारू रूप से' (यानी हिंसा, अत्याचार, जनता पर गोलीबारी, गिरफ्तारियां और फर्जी मतदान के रूप में समझ लेना चाहिए) संपन्न कराने के लिए केन्द्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 800 से ज्यादा कम्पनियां तैनात कर दीं। गौरतलब है कि इनमें से 600 से ज्यादा कम्पनियां पश्चिम बंगाल में भेजी जा रही हैं जहां माओवादी आंदोलन अपेक्षाकृत मजबूत है। चुनावों से काफी पहले से ही सीपीएम ने अपने गुण्डों की सेना हर्मद वाहिनी के हजारों हथियारबंद गिरोहों को खासकर जंगलमहल इलाके के दर्जनों गांवों में लगा दिया। इन हथियारबंद गुण्डा गिरोहों और संयुक्त बलों के पाशविक अत्याचार और अकथनीय हिंसा पहले से जारी है। इसका मतलब यह है कि वोट डालने से इनकार करने वाली जनता को बंदूक की नोक पर मतदान केन्द्रों पर हांक ले जाने तथा अभूतपूर्व स्तर पर भारी फर्जी मतदान करने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में सीपीएम बड़े पैमाने पर हिंसा और आतंक मचाने के लिए मुस्तैदी से तैयार है ताकि वह किसी न किसी तरीके से सत्ता पर बने रह सके।

सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन रहे या फिर जो भी पार्टी या गठबंधन चुनाव जीतकर सत्ता में आना चाहता हो, वे सभी सामंतों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के हितों को ही पूरा करेंगे न कि मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छात्रों, महिलाओं, दलितों आदि उत्पीड़ित वर्गों/तबकों की भलाई के लिए काम करेंगे जो आबादी का 95 प्रतिशत हैं। यह सच्चाई पिछले 64 सालों के तथाकथित स्वतंत्र भारत के इतिहास में साबित हो चुकी है। दरअसल यह चुनाव ही सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। यह लुटेरे वर्गों के शासन को पुख्ता करने वाला एक कवायद है। इन चुनावों से ज्यादा से ज्यादा शासक गिरोह के रंग में या उसकी पार्टी में बदलाव आ सकता है, मौजूदा व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव कतई नहीं आएगा। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी जनता की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं होगा। चुनावों में पूंजी के तौर पर पैसा ही लगाया जाता है। संसद और विधानसभा का संचालन भी पैसे वाले ही करते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी कई गुना पैसा कमाते हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टियों के उम्मीदवारों में हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन जुर्मों में लिप्त आपराधिक चरित्र वालों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी उनके स्वभाव को प्रतिबिम्बित कर रही है। इसीलिए हमारी पार्टी यह स्पष्ट करती है कि संसद और विधानसभाएं 'सुअरबाड़ों' के अलावा कुछ नहीं हैं। मौजूदा व्यवस्था को जड़ से बदले बिना जनता की जिंदगियां नहीं बदलेंगी। नई जनवादी क्रांति को सफल बनाकर मजदूर-किसान एकता के आधार पर तमाम शोषित जनता की जनवादी राजसत्ता का निर्माण करना ही एक मात्र विकल्प है। हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनता का आवाहन करती है कि वह इसके लिए हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध में शामिल हो।

प्यारे लोगो!

फिलहाल पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करें। 'लोकतंत्र' बताए जाने वाले देश में वोट डालने के अधिकार के साथ-साथ वोट नहीं डालने का अधिकार भी होना चाहिए। इस अधिकार के हनन के खिलाफ संघर्ष करें। सशस्त्र पहरे में जनता को बलपूर्वक मतदान केन्द्रों में हांक ले जाने के खिलाफ आवाज उठाएं। भ्रष्टाचार-घोटालों से सड़-गल चुकी इस ढोंगी संसदीय जनवादी व्यवस्था को ठुकरा दें। दण्डकारण्य, बिहार-झारखण्ड, ओड़िशा, बंगाल आदि जगहों पर हमारी पार्टी के नेतृत्व में प्राथमिक स्तर पर आकार ले रही जनता की जनवादी राज्य व्यवस्था का स्वागत करते हुए देश के चारों ओर जनता की राजसत्ता की स्थापना के लिए कमर कस लें।

Abhay

(अभय)
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)